बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्ष: 23 ○ अंक: 157 ○ नई दिल्ली ○ शुक्रवार 20 जून 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्य: 3 रूपया ○ पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

सोनिया गांधी की हालत में हो रहा सुधार, अस्पताल से आया नया अपडेट

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बीते रविवार से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। पेट से जुड़ी समस्या के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज सुबह नौ बजे सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की जानकारी अस्पताल की ओर से साझा की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, सोनिया गांधी की हालत स्थिर बनी हुई है। उनकी स्थिति कंट्रोल में है। सर गंगा राम अस्पताल में चिकित्सा दल की देखरेख में उनकी हालत में सुधार हो रहा है। सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं। उनका स्वास्थ्य स्थिर है और उनकी निरंतर देखभाल के तहत आज एक विशिष्ट आहार योजना शुरू की गई है। आगे कहा कि उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अभी उनकी छुट्टी की तारीख तय नहीं की गई है।

पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं, अखिलेश की भी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई हस्तियों ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। बृहस्पतिवार को राहुल 55 साल के हो गए। पीएम मोदी ने राहुल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के मूल्यों के प्रति उनके समर्पण और उन लाखों लोगों के प्रति संवेदना के लिए उनकी प्रशंसा की, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें अपना आदर्श भाई बताया। उन्होंने कहा कि जो खून से नहीं, बल्कि विचार, दृष्टि और उद्देश्य से जुड़े हैं। भारतीय ब्लॉक घटकों के नेताओं ने भी गर्मजोशी से बधाई दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और उनकी समावेशी और व्यापक सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं!÷ राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने भी गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गांधी के स्वस्थ, सफल, खुशहाल, लंबे और समृद्ध जीवन की कामना की। कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने गांधी की सराहना की और कहा कि बिना किसी डर के

फासीवादियों से मुकाबला करने का उनका साहस, नफरत पर प्यार की जीत का उनका संदेश और देश के गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और पिछड़ों के लिए उनकी दूरदर्शी सोच उन्हें ऐसा नेता बनाती है जिसकी भारत को इस कठिन दौर में जरूरत है।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ने राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा दी है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें भारत के विचार के लिए लड़ने वाल सिपाही बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि जिस हद तक वह इस देश में शोषितों औक वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वह वास्तव में अभूतपूर्व है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर गांधी की सराहना की। पार्टी ने कहा, आप न्याय के लिए एक सच्चे योद्धा हैं। आप बेजुबानों की आवाज हैं और समानता के लिए एक अथक समर्थक हैं। यह वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए और आप जिन आदर्शों के लिए खड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाने और उन बदलावों को लाने के लिए आपको नई ताकत मिले, जिनके लिए आप प्रतिबद्ध हैं।÷ भारतीय युवा कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी का जश्न मनाएं, जिनकी राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों के लिए आशा और ताकत लाती है।

बाटला हाउस के लोगों को बड़ी राहत, बुलडोजर एक्शन पर रोक, हटाए गए बैरिकेड

नई दिल्ली । दिल्ली के बाटला हाउस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल था. लेकिन, अब स्थिति कुछ शांत होती नजर आ रही है. डीडीए ने खसरा नंबर 279 पर बने घरों को अवैध बताते हुए 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ स्थानीय लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली है. खसरा नंबर 279 में कुल 34 बीघा जमीन है, जिसमें से केवल 2 बीघा और 10 बिस्वा पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं. डीडीए के नोटिस में स्पष्टता की कमी है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को फिलहाल हटा लिया है, जिससे इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है. दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला कई इलाकों में जारी है. हाल ही में अशोक विहार, वजीरपुर, मद्रासी कैंप और कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़ा गया. इन कार्रवाइयों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. आप का कहना है कि बीजेपी ने जहां झुग्गी, वहां मकान का वादा किया था, लेकिन अब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पुनर्वास योजना के तहत झुग्गीवासियों को पक्के मकान दे रही हैं. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बाटला हाउस के निवासियों को कोर्ट से मिली राहत ने फिलहाल बुलडोजर की तलवार को टाल दिया है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है.

पोस्को मामले के आरोपी को जमानत, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- पीड़िता के पलटे बयान

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में एक व्यक्ति को पोस्को अधिनियम के तहत बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली सरकार के सितंबर 2020 के निचली अदालत के फैसले को चुनोती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया. दरअसल यह मामला 12 साल से कम उम्र की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा था. जिसके तहत आरोपी पर पोस्को की धारा 9 और 10 के तहत मामला दर्ज

किया गया था. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी विश्वसनीय और ठोस आधार नहीं है, लिहाजा मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी अदालत से आरोपी को बरी किए गए फैसले में केवल तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब उस मामले में पर्याप्त और मजबूत कारण हो. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि निचली अदालत से आरोपी को बरी करने का फैसला उचित था. क्योंकि बच्ची और उसके माता-पिता के बयानों में बड़ा अंतर देखने को मिला था.

दिल्ली पुलिस के साइबर सेल का बड़ा खुलासा, 8 लाख की ठगी का मास्टरमाइंड जामताड़ा से गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के हब माने जाने वाले झारखंड के जामताड़ा से एक कुख्यात साइबर अपराधी अजय कुमार मंडल को अरेस्ट कर लिया. यह गिरफ्तारी कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर की गई जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम के बॉर्डर तक पुलिस की टीम पहुंची. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय कुमार मंडल खुद को बैंक अधिकारी बता कर लोगों को फोन करता था और KYC अपडेट के बहाने उनसे जानकारी हासिल करता था. इस गैंग से एक दिल्ली निवासी महिला को इसी तरीके से निशाना बनाकर उसके मोबाइल पर एनीडेस्क नाम का रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल कराया गया, जिसके जरिए आरोपी ने महिला के अकाउंट से करीब 8 लाख रुपये उड़ा लिए. इस रकम से आरोपी ने 7 महंगे एप्पल आईफोन और महंगे गैजेट्स जैसे हाई-एंड डिवाइस रिलायंस डिजिटल और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से खरीदे. अपनी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए इन आरोपियों ने डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल किया. गैंग ने फर्जी नाम से दर्ज सिम और मोबाइल नंबरों का नेटवर्क तैयार किया. लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फॉरेंसिक जांच के जरिए ढ्ढक्कलॉग्स, सिम के इस्तेमाल और IMEI नंबरों को ट्रैक कर लिया. एक बड़ा सुराग तब मिला जब झारखंड के गिरिडीह इलाके में 2 संदिग्ध मोबाइल नंबर एक ही समय और जगह पर एक्टिव पाए गए.

दिल्ली में बारिश के कारण सबसे साफ हवा वाला दिन, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली । ष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर में कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा। दिल्ली वालों को बुधवार 18 जून को प्रदूषण से भारी राहत मिली है। बीते आठ महीनों में दिल्ली में साफ हवा का रिकॉर्ड बना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो बुधवार को एक्यूआई गिरकर 81 के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में बीते 261 दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज हुई है। दिल्ली के मौसम में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मौसम में बदलाव के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। दिल्ली में बीते वर्ष सितंबर के महीने में दिल्ली में सबसे साफ हवा दर्ज हुई है। 29 दिसंबर 2024 को वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 अंक रिकॉर्ड हुआ था। इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य से 2.6 डिग्री कम दर्ज हुआ है। दिल्ली में शाम 5.30 बजे सापेक्ष आद्रता 94 फीसदी दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने 18 जून से 24 जून तक के लिए बाद छाए रह सकते है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।

निर्यात संचालित विकास रणनीति की विफलता

प्रभात पटनायक

ज्यां बेप्टिस्ट से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अठारहवीं सदी में अपना लेखन किया था। उन्होंने एक नियम सूत्रबद्ध किया था, जिसका आशय यह था कि 'आपूर्ति खुद अपनी मांग पैदा करती है।' इसका अर्थ यह था कि किसी अर्थव्यवस्था में मालों के समग्र उत्पादन की तुलना में, मांग की कमी या तंगी कभी हो ही नहीं सकती है। उनकी दलील इस प्रकार थी। किसी अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी पैदा होता है, वह इस उत्पादन से जुड़े लोगों के बीच उतनी ही मात्रा में आय पैदा करता है। इस आय का या तो उपभोग कर लिया जाता है या फिर इसकी 'बचत' कर ली जाती है यानी उपभोग नहीं किया जाता है। जितनी भी आय का उपभोग होता है, उससे उत्पादित उपभोग मालों की उतनी ही मांग पैदा होती है। और जितना भी हिस्सा बचा लिया जाता है, उसका या तो सीधे-सीधे पूंजी मालों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसे ऋण के तौर पर उन लोगों के हवाले कर दिया जाता है जो पूंजी माल खरीदना चाहते हैं यानी ऋण लेकर निवेश करना चाहते हैं। जो कुछ भी 'बचाया' जाता है तथा जो कुछ भी निवेश किया जाता है, अंततः ब्याज की दरों में समायोजनों के जरिए बराबर हो जाता है। इसलिए, इस तरह के समायोजनों के साथ, जो कुछ भी पैदा होता है, अंततः समग्रता में उसकी मांग आ जाती है और इसका कोई कारण नहीं बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम उत्पादन की यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में नहीं हो। बेशक, किसी बाजार विशेष में मांग और आपूर्ति का बेमेल होना तो संभव है, लेकिन समग्रता में ऐसा कभी नहीं होता है। से महाशय के इस नियम की समस्या यह है कि इसमें चालू समय में कमाई गयी आमदनियों में से सारी मांग को, चालू समय में पैदा हुए मालों की मांग के रूप में ही देखा जाता है, चाहे वह उपभोग के लिए हो या फिर अपनी संपदा में बढ़ोतरी करने यानी निवेश के लिए हो। लेकिन, अगर संबंधित लोग अपनी संपदा में पैसे के रूप में बढ़ोतरी करना चाहते हों यानी वे अपनी संपदा को आंशिक रूप से मुद्रा के रूप में भी रख रहे हों, जोकि वर्तमान समय में पैदा होने वाला माल नहीं होता है (मिसाल के तौर पर अगर वे अपनी चालू आय में एक हिस्सा मुद्रा के रूप में रखना चाहते हों) तो इसका कोई कारण नहीं होगा कि वर्तमान समय में उत्पादित मालों की अपूर्ति, अपने बराबर मांग पैदा कर रही हो। माल-धन-माल के चक्र में, अगर लोग धन को माल में नहीं तब्दील करना चाहते हों, तो माल के यानी उत्पादित मालों के अधिउत्पादन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अपर्याप्त मांग के ऐसे हालात में, उत्पादित मालों के मुद्रा मूल्य में अगर कोई कमी होती है, तो उससे तो संपदा के रूप के तौर पर मुद्रा की मांग ही पुख्ता होगी और इसलिए अधिउत्पादन की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही होगी। मुख्यधारा का पूंजीवादी अर्थशास्त्र, जो से के नियम को सच मानता है, यह मानकर चलता है कि लोग कभी भी संपदा के रूप के तौर पर पैसा अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि धन तो सिर्फ लेन-देन या सर्कुलेशन का माध्यम होता है, पर कभी भी संपदा के रखे जाने का रूप नहीं होता है।

लेकिन, यह एक बेतुकी पूर्व-धारणा है। यह न सिर्फ व्यावहारिक रूप से गलत है बल्कि तार्किक रूप से भी चलने वाली बात नहीं है। इसीलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में से का नियम, एक बेतुकी पूर्व-धारणा था कार्ल मार्क्स ने से के नियम को और एक अर्थशास्त्री के नाते जेबी सायस को (जिन्हें वह 'घिसे पिटे' मोन्सेयर से कहा करते थे) खूब आड़े हाथों लिया था और पूंजीवाद के अंतर्गत अधिउत्पादन के संकटों की संभावना की प्रस्थापना की थी। हम अर्थशास्त्र की इतनी पुरानी बहसों की बात क्यों कर रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ मार्क्स ने निपटा दिया था बल्कि जिन्हें 1930 के दशक में एक बार फिर से, महामंदी के समय पर हुई, पूंजीवादी अर्थशास्त्र में केन्सवादी क्रांति ने निपटा दिया था। उन हालात में यह दलील देना ही हद दर्जे की बेहूदगी होता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उत्पादित मालों की सकल मांग की तंगी कभी हो ही नहीं सकती है। केन्स पश्चिमी पूंजीवाद को बोल्शेविक शैली की क्रांति से बचाना चाहते थे और उन्होंने यह पहचाना था कि ऐसा करने के लिए हमें पहले तो पूंजीवाद की विफलताओं को स्वीकार करना होगा और उनसे उबरने के लिए इस व्यवस्था की ही मरम्मत करनी होगी, ताकि क्रांति की संभावनाओं को रोका जा सके। हम से के नियम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बीच आर्थिक विमर्श में इस नियम की दबे पांव वापसी हो गयी है। से के नियम की इस वापसी की खामोशी, उसे जितना प्रभावशाली बनाती है, उतना ही कपटपूर्ण भी बना देती है। वास्तव में समूची नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था का तर्क ही से के नियम की वैधता को मानकर चलने पर आधारित है। नव-उदारवाद के लिए और तब तक चलती आ रही नियंत्रणात्मक रणनीति के त्यागे जाने के लिए (भारत में नियंत्रणात्मक रणनीति को अक्सर नेहरू-महालनबीस रणनीति के नाम से जाना जाता है) बौद्धिक आधार, सत्तर के दशक के आरंभ में तैयार किया गया था। उस समय यह दलील दी जाती थी कि चार पूर्वी एशियाई टाइगरोंङ्क दक्षिण कोरिया, ताईवान, हांगकांग तथा सिंगापुरङ्क ने, उल्लेखनीय रूप से ऊंची आर्थिक वृद्धि दरों का प्रदर्शन किया था, जो नियंत्रणात्मक रणनीति का अनुसरण कर रहे भारत जैसे देशों के मुकाबले कहीं बहुत ऊंची दरें थीं। और अगर ये अन्य देश भी नियंत्रणात्मक रणनीतियों का त्याग कर देते हैं या विश्व बैंक की शब्दावली में अपनी 'अंतर्मुखी' विकास रणनीति को छोड़ देते हैं और उसकी जगह पर 'निर्यात संचालित वृद्धि' का रास्ता अपना लेते हैं, तो वे भी इन एशियाई टाइगरों की ही तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह एक बेतुकी दलील थी। अगर विश्व सकल मांग का स्तर किसी खास दर से बढ़ रहा है, तब सभी देशों को मिलाकर उत्पादन का स्तर, उससे ऊंची दर से नहीं बढ़ सकता है। अगर कुछ देशों का उत्पाद विश्व की सकल मांग की वृद्धि दर से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, तो यह इसीलिए संभव होगा कि अन्य देशों का उत्पाद कहीं धीमी दर से बढ़ रहा होगा। अगर पहले धीमी गति से वृद्धि कर रहे देशों की उत्पाद वृद्धि दर बढ़ती है, तो यह उन देशों की कीमत पर ही हो सकता है, जिनकी वृद्धि दर पहले अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रही हो। इसलिए, यह लालच देना ही बेतुका था कि सभी देश 'एशियाई टाइगरों' वाली रफ्तार से बढ़ सकते हैं, बशर्ते वे एक 'निर्यात-संचालित' वृद्धि रणनीति अपना लें। ऐसी दलील देना सकल मांग की सीमाओं को अनदेखा करना यानी से के नियम को सत्य मानकर चलना था। इस तरह, नेहरूवादी रणनीति के त्यागे जाने की पुकार के पीछे, से के बेतुके नियम का सहारा लिया जा रहा था। बहरहाल, से के नियम का यह सहारा लिया जाना, एक आवरण में किया जा रहा था और इसीलिए यह कामयाब रहा था। इस आवरण ने एक 'लघु देश धारणा' का रूप लिया था। कोई छोटा देश, ठीक अपने छोटा होने की वजह से, अपेक्षाकृत बड़े देशों की कीमत पर कहीं ज्यादा निर्यात कर सकता था और इस तरह ज्यादा निर्यात कर सकता था कि उन्हें इस पैमाने पर नुकसान हो ही नहीं, जोकि ध्यान में आ सकता हो। इसलिए, छोटे देशों के लिए इस धारणा की फिर भी कुछ तुक बनती है कि वे अगर चाहें तो ज्यादा निर्यात कर सकते हैं यानी उनके सामने मांग की कोई उल्लेखनीय सीमा है ही नहीं। और छोटे देश अक्सर ऐसी धारणा लेकर चलते हैं। लेकिन, 'निर्यातोन्मुखी वृद्धि' की नव-उदारवादी रणनीति तो इसका स्वांग भरते हुए सभी देशों के गले उतरवाने की कोशिश की जा रही थी कि उनमें से हरेक, किसी 'छोटे देश' की तरह आचरण कर सकता था। यह पूरी तरह बेतुकी बात थी।

यह जोड़ने की उलट भ्रांति का नंगा मामला था और से के नियम की चोर दरवाजे घुसपैठ का मामला। बेशक, चार एशियाई टाइगरों की कामयाबी के बाद, चीन में तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में और भी शानदार वृद्धि दर सफलताएं देखने को मिली थीं। हां! यह जरूर है कि ये अनिवार्य रूप से नव-उदारवादी रणनीति की मिसालें नहीं थीं और ना ही ये शुद्ध रूप से तथा सरल तरीके से ''निर्यातोन्मुखी वृद्धि'' की मिसालें थीं। और जिस हद तक ये निर्यात की कामयाबियां थीं, यह बहुत हद तक इसका नतीजा था कि पश्चिमी विकसित देशों की पूंजी ने, पश्चिमी विकसित देशों के बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए, इन देशों की धरती पर अपने कारखाने लगाने का फैसला लिया था। दूसरे शब्दों में उनकी सफलता के सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि विकसित देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर धीमी हुई थी, हालांकि ऐसा उनकी महानगरीय पूंजियों के साथ नहीं हुआ था। और इस तथ्य का तो जिक्र ही क्या करना कि तीसरी दुनिया के अन्य देश, दौड़ से बाहर ही छूट गए थे। फिर भी यह देशों के बीच दौड़ तो थी। झूठे तरीके से, से के नियम को मानने के जरिए, 'निर्यात संचालित वृद्धि' की रणनीति ने देशों को, और खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों को, एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मिसाल के तौर पर भारत, वस्त्रों का अपना निर्यात बढ़ा तो बांग्लादेश की कीमत पर ही सकता था। पलटकर इसका अर्थ यह था कि कोई देश कम मजदूरी देने के जरिए, उनसे ज्यादा घंटे तक काम कराने के जरिए और फर्जीवाड़े के जरिए उनके वैध भुगतानों को छीनने के जरिए, अपनी कामगार आबादी को जितना ज्यादा निचोड़ने में सफल रहेगा, उतना ही ज्यादा वह अपनी निर्यात की मुहिम में सफल रहेगा।

सम्पादकीय...

भारतीय सिखों ने की मोदी के खिलाफ खालिस्तानी प्रदर्शन की निंदा

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे। उनके दौरे से पहले जिस प्रकार वहां खालिस्तानी संगठन सिख फार जस्टिस के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया उसकी संसार भर के सिख समाज के लोगों द्वारा सख्त शब्दों में निन्दा की जा रही है। अक्सर खालिस्तानी समर्थक भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, मगर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उनके द्वारा छोटे-छोटे सिख बच्चे जिनकी पढ़ने-लिखने की उम्र है उनका ब्रेनवॉश करके उनसे नारेबाजी करवाई गई। कैनेडा से एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत के सिखों में नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने कैनेडा सरकार और प्रशासन से खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को पुख्ता बनाने की अपील की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ सिख बच्चे पीएम मोदी और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के पूर्व सदस्य हरपाल सिंह कोछड़ ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस छोटी उम्र में जो उनसे कहा जाता है वो वही करते हैं, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि कुछ लोग बच्चों से ऐसी गलत हरकत करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा गुरु साहब ने हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। बच्चों का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, जिसने भी यह शरारत की है हम उसकी निंदा करते हैं, जो भी बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हैं, इससे उनके मंसूबें सिख धर्म को बदनाम करने वाले प्रतीत होते हैं। खालिस्तानी संगठन सिख फार जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इसमें उसने कहा कि हम जी-7 शिखर सम्मेलन में मोदी की राजनीति खत्म करने के लिए तैयार हैं। इस बीच सरकार ने हालात को देखते हुए कानानास्किस में नो फ्लाई ज़ोन घोषित कर दिया। इसके अलावा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, प्रांतीय पुलिस और कनाडाई सशस्त्र बलों द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि, सभी सिख संगठन इस प्रदर्शन के समर्थन में नहीं दिखे। कैनेडा के आम सिखों ने खालिस्तानी प्रदर्शनों की निंदा की और पीएम मोदी के दौरे को भारत-कनाडा संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर बताया। इस प्रदर्शन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जी-7 जैसे मंच का दुरुपयोग है। दूसरी ओर, कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने भारत को जी-7 में आमंत्रित करने का बचाव करते हुए भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। निहंगों द्वारा महिला यूट्यूबर की हत्या का मामला गर्माया – हाल ही में निहंग पहरावा पहने हुए अमृतपाल सिंह मेहरों और उनके साथियों के द्वारा बठिंडा में एक महिला यूट्यूबर कमलप्रीत कौर को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद संसार भर से सिखों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ज्यादातर सिख समाज के लोग इस घटना की पुरजोर निन्दा करते दिख रहे हैं। उनका मानना है कि हर महिला को अपनी ज़िन्दगी अपने हिसाब से जीने का हक है फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत अमृतपाल सिंह मेहरों को हुई तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, इस प्रकार तालिबानियों की भांति किसी की हत्या करना किसी भी तरह से सही नहीं है। उनका मानना है कि गुरु गोबिन्द सिंह जी ने जब लाडली फौज तैयार की थी तो उन्हें सख्त हिदायत भी दी थी जिसमें किसी भी निहत्थे पर वार न करना, महिलाओं का सम्मान करना की बात कही गई थी। वहीं कुछ लोग खुलकर अमृतपाल सिंह मेहरों को सही ठहराते हुए महिला यूट्यूबर को गलत ठहरा रहे हैं, कुल मिलाकर यहां भी सिख समाज दो गुटों में बंटा दिखाई दे रहा है। आखिरकार बाला साहिब अस्पताल संगत के सुर्पुद हुआ – दिल्ली का बहुचर्चित बाला साहिब अस्पताल जो कि कई साल पहले ही शुरू हो जाना था मगर सिख जत्थेबं?दियों की राजनीति की भेंट चढ़कर रह गया। बीते समय में जब दिल्ली में सरना बंधुओं का कार्यकाल था उस समय अस्पताल बनकर तैयार हो गया था और प्राईवेट कंपनियों की मदद से इसे शुरू भी किया जा रहा था जिसमें कंपनियों के साथ करार किया गया था कि जरूरतमंद सिख परिवारों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा, मगर उस समय बादल गुट के द्वारा अस्पताल को केवल इसलिए शुरू नहीं होने दिया, क्योंकि इसका पूरा लाभ सरना गुट को मिलना था, जिसके चलते प्रकाश सिंह बादल के कहने पर कोर्ट केस बादल समर्थकों के द्वारा किए गए और अस्तपाल खण्डर बनकर रह गया। उसके बाद जब दिल्ली में कोविड का दौर आया तो उस समय दिल्ली कमेटी द्वारा एक प्रयास करते हुए इसे कोविड वार्ड के तौर पर अस्थाई रूप से तैयार किया गया। उसके बाद डायलिसिस सेंटर खोला गया जिसकी विशेषता यह रही कि उसमें कोई भी फीस काउंटर ही नहीं रखा गया। प्रबन्धकों का दावा है कि अभी तक इसमें 90 हजार के करीब डायलेसिस की जा चुकी हैं। कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो के विशेष प्रयासों से 50 बैड के अस्पताल को काफी पहले तैयार कर लिया गया था मगर सरकारी मंजूरी न मिलने के चलते अभी तक इसे शुरू नहीं किया जा सका था और अब भाजपा सरकार के आते ही मनजिन्दर सिंह सिरसा जो कि सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने इसे शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई। उनके सहयोग से सभी तरह की परमिशन दिलवाकर अस्पताल को शुरू करवा दिया है। इसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं पहुंचने वाली थी। मगर अहमदाबाद हादसे के चलते वह नहीं आई। मनजिन्दर सिंह सिरसा कार्यक्रम के मंच पर तो आए मगर उद्घाटन से पहले ही निकल गए। कार सेवा वाले बाबा बचन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा हरबंस सिंह जी के श्राप के कारण अस्पताल खण्डहर बनकर रह गया था। पंजाबियों को रेखा सरकार से उम्मीदें -दिल्ली में पंजाबी भाषा के साथ पिछली सरकारों के द्वारा हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा जिसके चलते भाषा को काफी नुक्सान भी हुआ, मगर नई सरकार से समूचे पंजाबियों और खासकर पंजाबी भाषा के प्रचार और प्रसार में लगी संस्था 'पंजाबी हेल्पलाइन' को काफी उम्मीदें हैं। संस्था के मुखी प्रकाश सिंह गिल ने रेखा गुप्ता सरकार से नीतियों में बदलाव कर पंजाबी भाषा से जुड़े मुद्दों का हल निकालने की अपील की है।

ट्रेडर ट्रम्प को मोदी की खरी-खरी

वैश्विक जटिल परिस्थितियों में पूरा विश्व बहुध्रुवीय हो चुका है। बहुध्रुवीय इस दुनिया में वही देश अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जिनमें दम होगा। जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी कर भारत की ताकत, महत्व और कुशल नेतृत्व का प्रमाण दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी-7 समूह के वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं करके अमेरिका लौट गए। क्योंकि जर्मन द्वारा तैयार किए गए वक्तव्य पर उन्हें आपत्ति थी। जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच फोन पर 35 मिनट तक बात हुई। इस कॉल का आग्रह ट्रम्प की तरफ से ही किया गया था। दोनों में पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भारत-पाकिस्तान सीज फायर को लेकर जारी रस्साकशी के बीच विस्तार से बात हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को दो टूक शब्दों में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर न तो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा और न ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई चर्चा हुई। ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आकर मुलाकात करने का आग्रह किया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तय कार्यक्रमों के चलते अमेरिका आने में असमर्थता जताई। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था और भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। भारत का एक्शन बहुत ही संतुलित और सटीक था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रोक्सी वॉर नहीं युद्ध के रूप में देखेगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-पाकिस्तान सीज फायर को लेकर कई तरह के दावे? किए थे और कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। जिस पर भारत ने कड़ा प्रोटेस्ट जताया था। इसके बावजूद ट्रम्प शब्दों को बदल-बदल कर अपना बयान दोहराते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक आतंकवादी देश पाकिस्तान को महान राष्ट्र तक बता दिया और अमेरिकी सेना के एक उच्च अधिकारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपना प्रमुख सहयोगी बताया। पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण दिलवाने में भी ट्रम्प ने सहयोग किया। ?इतना ही नहीं बुधवार की दोपहर ट्रम्प ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के साथ वाशिंगटन में दोपहर भोज भी किया। पाकिस्तान के प्रति ट्रम्प के रुख में आए भारी बदलाव से चौंकना मुश्किल नहीं है। 2018 में ट्रम्प ने पाकिस्तान को ÷झूठ और धोखे÷ का देश करार दिया था और गर्व से कहा था कि अमेरिका ने अरबों डॉलर की सहायता रोक दी है। हालांकि, अब वह पाकिस्तान को ÷महान राष्ट्र÷ कहते हैं और ÷व्यापार में काफी वृद्धि÷ का वादा किया है। कोई यह पूछे बिना नहीं रह सकता कि आखिर क्या बदल गया? ज़मीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने और चरमपंथ की आग को हवा देने के लिए ज़िम्मेदार है। यह भी न भूलें कि भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के बाद हाल ही में पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारी एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष हिंदुओं की मौत हो गई थी, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी संगठनों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। यह रुख बदलने वाला नहीं है और पाकिस्तान के लिए व्यापार में कोई भी वृद्धि केवल शत्रुतापूर्ण दक्षिण एशियाई देश के आतंकवादी प्रयासों को बढ़ावा देने वाली है। डोनाल्ड ट्रम्प इस समय लीडर की बजाय पूरी तरह ट्रेडर बने हुए हैं। मीडिया में ऐसी रिपोर्टें उछल रही हैं कि एक अमेरिकी कम्पनी जिसमें उनका बेटा पार्टनर है, ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की है। ट्रम्प का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अफगानिस्तान, तालिबान और चीन को लेकर भी है और अब इसमें ईरान को लेकर चिंताए भी जुड़ गई हैं। पूरी दु?निया जानती है कि अफगानिस्तान पर हमले के समय अमेरिका ने पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान ने अमेरिका की फंडिंग का इस्तेमाल आतंकवाद को सींचने में किया। ट्रम्प यही सोच रहे होंगे कि अमेरिका अगर ईरान के विरुद्ध युद्ध में कूदेगा तो उन्हें पाकिस्तान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वह पाकिस्तान और भारत से अलग-अलग डील कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रम्प पाकिस्तान के साथ व्यापार के बारे में सोच रहे हैं। क्या अमेरिका पाकिस्तान को ?फिर से हथियार बेचने जा रहा है जैसा कि वह पहले करता रहा है। यह लेन-देन की कूटनीति का एक और उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को खरी-खरी कहकर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे दिया है। मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान भारत-कनाडा संबंध एक बार फिर पटरी पर आ गए हैं। दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध फिर से सामान्य बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अब एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त बहाल होंगे और दोनों देश व्यापार, लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क और रुकी हुई ट्रेड वार्ता पर बातचीत शुरू करेंगे। कनाडा ने भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का समर्थन किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का दौरा एक कूटनीतिक सफलता है।

दुनिया में कोई फ्री में नहीं खिलाता, व्हाइट हाउस में ट्रंप की रोटी खाते ही मुनीर को यह बात समझ आ गयी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ दोपहर का भोज करके पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं बल्कि सेना ही असली ताकत रखती है। ट्रंप ने जिस तरह से असीम मुनीर को खाना खिलाते समय कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है उससे यह भी संकेत मिले कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। हम आपको याद दिला दें कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को उखाड़ने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था। चूंकि ईरान की सीमाएं भी पाकिस्तान के साथ लगती हैं इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर उसे अपना बेस वहां बनाने दे ताकि उसके लड़ाकू विमान वहीं से उड़ान भर सकें। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में इस बात की इजाजत वहां की सरकार नहीं बल्कि सेना ही दे सकती है इसलिए मुनीर को लंच पर बुलाया गया। इसके अलावा इजराइल भी चाहता है कि ईरान को किसी भी मुस्लिम देश की मदद नहीं मिले, इसके लिए उसने अमेरिका से पाकिस्तान को समझाने के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं और हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान पर हुए इजराइली हमलों की निंदा की है इसलिए ट्रंप यह सुनिश्चित कर रहे थे कि पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आये। इसके अलावा ट्रंप का एक और गेम प्लान यह था कि वह मुनीर को लंच कराने के दौरान उनकी भेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवा दी जाये लेकिन मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चाल समझ गये थे इसलिए उन्होंने कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका में कुछ समय रुकने का उनका आग्रह ठुकरा दिया था। मोदी समझ गये थे कि यदि ट्रंप ने अचानक उनकी और मुनीर की भेंट करवा कर दुनिया के सामने फिर से यह दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवा दी है तो उनके लिए घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर नई मुश्किल खड़ी हो जायेगी। जहां तक ट्रंप और मुनीर के लंच की बात है तो बताया जा रहा है कि पहला निवाला मुंह में डालते ही मुनीर के होश उड़ गये क्योंकि वह कट्टरपंथी स्वभाव के हैं इसलिए उन्हें यह बात रास नहीं आई कि वह ईरान का साथ देने की बजाय इजराइल को अपना मिशन पूरा करते हुए देखें। मुनीर को ट्रंप की रोटी खाते ही यह बात समझ आ गयी कि दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ नहीं खिलाता। वैसे भी ट्रंप राजनीतिज्ञ कम, व्यापारी ज्यादा हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के किसी भी सेनाध्यक्ष को मुंहमांगी कीमत देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। यही काम ट्रंप ने किया और मुनीर को अपने पाले में कर लिया। वैसे, अमेरिकी राजनीति के इतिहास में यह दुर्लभ ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व घटना है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी सैन्य प्रमुख को लंच पर बुलाए। हालांकि अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी सैन्य नेताओं ने अतीत में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी।

51वें जी-7 शिखर सम्मेलन 15-17 जून 2025 कनाडा में भारत का आगाज़

वैश्विक स्तरपर भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का डंका पूरी दुनियाँ में बज रहा है,जिसका सटीक उदाहरण अभी 17 जून 2025 को माननीय भारतीय पीएम द्वारा जी-7शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन कनाडा पहुंचे व सम्मेलन अटेंड किया, हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी 2019 से लगातार एक विशिष्टता से आमंत्रित हो रहे हैं। सम्मेलन में भाग लेकर वैश्विक विकसित देशों से चर्चा कर विश्व को अपने अनुभव साझा कर रहा हैं,ताकि पूरी दुनियाँ की बेहतरीन के लिए बेहतर योगदान दिया जा सके। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीएम को जी-7 में आमंत्रित किया गया जिससे हम उन सटीक अंदाज लगा सकते हैं कि, भारत की प्रतिष्ठा में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र से आज दिन भर इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर माननीय पीएम के कनाडा पहुंचने से लेकर अंत तक नजर गाड़ाए राखी। सम्मेलन के दौरान हर विकसित देश माननीय पीएम से मिलना चाहता था,भारत से नजदीकियां बनाए रखने के भाव बड़े-बड़े नेताओं में देखे जो रेखांकित करने वाली बात है। चूँकि भारत का 51 वें जी-7 शिखर सम्मेलन 15-17 जून 2025 कनाडा में भारत का आगाज हुआ इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत भविष्य में जी-7 का सदस्य बन सकता है,क्योंकि भारत आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक ताकत बनकर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। साथियों बात अगर हम जी-7 सम्मेलन 2025 कनाडा के प्रमुख बिंदुओं और उद्देश्यों को समझने की करें तो, जी-7 देश भारत को एक ऐसे शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखते हैं, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब दे सकता है. भारत क्वाड समूह (भारत, अमेरिका,जापान,औरऑस्ट्रेलिया) का हिस्सा है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्णहै,दरअसल 2019 से भारत के पीएम को दुनिया के अमीर देश अपनी बैठक में हर साल बुलाते हैं, यह भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा 14 मई, 2023 को प्रकाशित लेख, जिसका शीर्षक है इंडिया ह्वाइ ऑलवेज इन्विटेड टू जी-7. व्हाई इज डैट सो इम्पोर्टेन्ट? ने भी भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस किया था,लेख में अनुमान लगाया गया है कि भारत भविष्य में जी-7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि, भारत की ओर से कुछ हिचकिचाहट हो सकती है। जी-7 2025 के एजेंडा के प्रमुख बिंदु–(1) वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी की आशंका, वैश्विक व्यापार में असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा (2) ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल संक्रमणआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, नेट-ज़ीरो लक्ष्यऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए नवीकरणीय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन पर बल (3) शांति और सुरक्षा, इज़राइल -ईरान संघर्ष, यूक्रेनङ्करूस युद्ध, आतंकवाद उन्मूलन, साइबर सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता और शरणार्थियों के संरक्षण पर चर्चा, जी-7 देश भारत को एक ऐसे शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखते हैं, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब दे सकता है। जी-7 के प्रमुख उद्देश्य (1) वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बढ़ावा देना (2) वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग (3) जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर नेतृत्व(5)वैश्विक स्वास्थ्य (जैसे कोविड -19) के संकट में सहयोग (6) लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन, कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में जी7 समिट का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी अब तक 6 वर्ल्ड नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज, द. अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया राष्ट्रपति लीजे म्युंग शामिल हैं। साथियों बात अगर हम भारत की बढ़ती भूमिका उपस्थित प्रतिष्ठा को समझने की करें तो,(1)भारत इस साल ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हैतमाम वैश्विक संस्थाओं का मानना है कि भारत एक साल के अंदर ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पा सकता है, जी 7 देश, जो विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह हैं, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं, कनाडाई पीएम ने शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत का होना आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं के लिए जरूरी है क्योंकि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है (2)-जिओ पोलिटिकल महत्व, भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और एक उभरती हुई शक्ति है, जी-7 देश भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं, जो चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है,भारत का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में, जी-7 के लिए महत्वपूर्ण है (3)-ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व-भारत को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख आवाज माना जाता है,जी 7 देश, जो मुख्य रूप से विकसित देश हैं, भारत जैसे उभरते देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं,भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023) ने इसे और मजबूत किया, जिससे जी7 को भारत की राय को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया, हडसन इंस्टिट्यूट के लेख में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के 2022 के बयान का हवाला देते हुए लिखा गया कि यूरोप को यह मानसिकता छोड़नी होगी कि यूरोप की समस्याएँ विश्व की समस्याएं हैं, लेकिन विश्व की समस्याए यूरोप कीसमस्याएं नहीं हैं. भारत की जी-20 अध्यक्षता और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन (2023) ने इसे ग्लोबल साउथ के हितों को जी-7 जैसे मंचों पर उठाने में सक्षम बनाया है। (4) वैश्विक चुनौतियों में योगदान--जी-7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और अंतराष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा होती हैय भारत इन क्षेत्रों में अपनी नीतियों और तकनीकी प्रगति (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था) के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हैइसके साथ ही भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, जी-7 के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मैच करता है. यह इसे उन देशों से अलग करता है जो जी-7 के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं, जैसे कि चीन।(5) मोदी की व्यक्तिगत छवि--2019 से हर जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया है (2020 को छोड़कर, जब कोविड-19 के कारण शिखर सम्मेलन रद्द हुआ था). यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और मोदी के नेतृत्व में भारत की सक्रिय विदेश नीति को दर्शाता है।पीएम की वैश्विक मंचों पर सक्रियता और उनकी कूटनीतिक पहल (जैसे जी-20 में भारत की भूमिका) ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया है. जी-7 देश भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी के साथ सीधे संवाद को महत्व देते हैं(6) चीन के मुकाबले भारत की रणनीतिक भूमिका--आज अमेरिका सहित पूरे पश्चिम की सबसे बड़ी चिंता चीन है. इसका कारण चीन की नीतियां तो अफेंसिव हैं हीं , चीन में लोकतंत्र का न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, हडसन इंस्टिट्यूट के लेख में तर्क दिया गया है कि भारत एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो चीन जैसे अधिनायकवादी देशों के प्रभाव को संतुलित कर सकता है, उदाहरण के लिए, दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2016 में खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने इसे नजरअंदाज किया. इसके विपरीत, भारत ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है,जी-7 देश भारत को एक ऐसे शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखते हैं, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब दे सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

तदर्थ शिक्षकों के पेंशन का रास्ता साफ -जगदीश पाण्डेय

हाटा,कुशीनगर ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की एक कार्यशाला का आयोजन श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय,हाटा,कुशीनगर के आडिटोरियम में प्रदेशीय उपाध्यक्ष जगदीश पाण्डेय के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। श्री पाण्डेय ने अपने सम्बोधन में बताया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान सरकार शिक्षक और कर्मचारियों के हित पर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर देती है,इसबार भी वही की।पुनः सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चैलेंज किया।सरकार ने स्पेशल अपील योजित किया।इस रिट में सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी।दलील पर दलील दी।पर सत्य को पराजित करना आसान नहीं।माननीय डबल बेंच ने भी सरकार की समस्त दलीलों को नियम विरुद्ध साबित करते हुए दिनाँक 01-05-2025 को निर्णय देते हुए सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने सम्यक सुनवाई करते हुए, सरकार के पक्ष और दलीलों को नियमों और विनियमों के विपरीत मानते हुए,सरकार के विशेष अपील को दिनाँक 16-06-2025 को दिए आदेश से *खारिज* करते हुए,माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच

के आदेश के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए पेंशन आदि देयकों को देने के आदेश को बरकरार रखा। शिक्षक साथियों ,यह संघर्ष की जीत है। न्याय की जीत है। कानून की जीत है। तदर्थ शिक्षकों ने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दीं हैं।उनका हक किसी भी कीमत पर छीनने वाले कभी भी सफल नहीं होंगें।हम प्रथम दिन से इस संघर्ष में अग्रणी रहें हैं।भाई शिव कुमार शुक्ल और उनकी पूरी टीम को बधाई।हमें उम्मीद है,सरकार समस्त तदर्थ शिक्षकों के हक और हुक़ूक़ को प्रदान करेगी वरना संघर्ष तो हमारी ताकत है।हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कार्यशाला को जिलाध्यक्ष साहित्यविद नन्दा पाण्डेय, जिलामन्त्री डॉ0 संजय कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष गोरखपुर दिलीप सिंह, जिलाध्यक्ष देवरिया आनन्द शंकर उपाध्याय, प्रधानाचार्य जगदम्बा पाण्डेय, अशोक पाण्डेय, ध्रुव जी गुप्त, प्रदेशीय पदाधिकारी गंगेश्वर पाण्डेय, पद्मिनी श्रीवास्तवा, जय प्रकाश शुक्ल, राधेश्याम श्रीवास्तव ,स्मृति श्रीवास्तव, लूसी एंजिलों, रीना श्रीवास्तवा,मोहन पाण्डेय, संजय पाण्डेय,डॉ0 वीरेन्द्र प्रताप शाही,सुजीत तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने भी सम्बोधित किया। सभी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। कार्यशाला राष्ट्र गान के गायन के साथ सम्पन्न हुआ।

एक नजर

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना को अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को किया गया जागरूक

पडरौना (कुशीनगर) । पूर्वांचल व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के द्वारा नगर के जायसवाल विवाह भवन में जागरूकता कार्यक्रम में व्यापारियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए योजनाओं की जानकारी में उद्योग लगाने के लिए जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार और जिला उद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने कहा कि आचार निर्माण, पापड़ निर्माण, चिप्स, सेवई, हल्दी, मसाला, केक, पशुआहार उद्योग, मछली आहार उद्योग, आटा चक्की, साबूदाना निर्माण, मिर्च पाउडर, घी उद्योग आदि खाद्य पदार्थ से संबंधित अन्य निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दिया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी विजय प्रकाश पांडेय, प्रदीप कुमार पाण्डेय,अमित यादव डीआरपी, लालता प्रसाद, पूनम जायसवाल महिला जिलाध्यक्ष, नाथू सिंह पटेल प्रदेश महामंत्री, संतोष यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोहन सिंह पटेल, राजन पटेल, राजकुमार गुप्ता, रवि सिंह लखनऊ प्रभारी, विनय जायसवाल, संजय यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे संचालन प्रमोद साह ने किया।

हिरनही टोला में एक रात में सात घरों में चोरी

10 लाख की संपति, नकदी और जेवरात समेत कई सामान चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के नाहर छपरा के इनरही टोला में बुधवार रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सात घरों को निशाना बनाया। चोर करीब दस लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत और पुलिस के प्रति आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार चोरों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। संजय कुशवाहा के घर में चोर छत के रास्ते घुसे और पचास हजार रुपए नकद व सात थान सोने-चांदी के जेवरात उड़ा ले गए। शैलेश के घर का मेन गेट तोड़कर एक लाख रुपए नकद और सात थान जेवर चोरी किए गए। वहीं, राजेश के घर से जंगला तोड़कर बीस हजार रुपए चुराए गए। प्रमोद के घर से तीस हजार रुपए, हरिकिशुन के घर से चालीस हजार रुपए और पांच थान जेवरात गायब हुए। दिनेश के घर से आठ हजार रुपए और पांच थान जेवरात चोरी हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने दिनेश के घर में शौच भी किया, जिससे उनकी बेखौफी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामनरेश के घर से एक लाख रुपए नकद और दो थान सोने के जेवरात भी चोरी हुए।ग्रामीणों का आक्रोश वारदात के समय अधिकांश घरों में पुरुष सदस्य मौजूद नहीं थे और महिलाएं ही घर पर थीं। चोरों ने चोरी के दौरान घर में सो रहे लोगों के कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया, ताकि किसी को भनक न लगे। सुबह जब लोग उठे तो घरों का सामान बिखरा पड़ा मिला और ताले टूटे हुए थे।इस संबंध में पडरौना कोतवाल रवि राय का कहना है कि मामला संज्ञान में है, लेकिन अभी तक किसी पीड़ित ने तहरीर नहीं दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा।

हज़रत मक़बूल शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत के साथ सम्पन्न

जौनपुर ।

राजा साहब का पोखरा, उत्तरी क्षेत्र जौनपुर में हज़रत मक़बूल शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 19 जून को बड़ी अकीदत, मोहब्बत और धार्मिक जोश के साथ मनाया गया। इस मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और मज़हबी भाईचारे की मिसाल पेश की। उर्स का आयोजन जनाब मुनीर हसन उर्फ दुलारे और जनाब इमरान खान की सरपरस्ती में किया गया। उर्स की शुरुआत फातिहा ख्वानी से हुई, जिसके बाद हज़रत की मजार शरीफ पर फूलों से बनी चादर चढ़ाई गई। इस दौरान सूफियाना कलाम, कव्वाली और नातिया नज़्मों की महफ़िल ने माहौल को रूहानी बना दिया। लोग दूर-दराज़ से आकर हज़रत से मन्नतें मांगते हैं और दिली सुकून हासिल करते हैं।

इस मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और मज़हबी भाईचारे की मिसाल पेश की।

बताया गया कि यह उर्स मुबारक 1994 से निरंतर हर साल इस्लामी माह चाँद की 22 तारीख को आयोजित होता आ रहा है। यह महज़ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक समरसता का प्रतीक भी बन चुका है, जिसमें हर मज़हब और समुदाय के लोग शरीक होते हैं। कार्यक्रम में इश्तेयाक़ अहमद उर्फ़ के डी, इक़बाल (बाबू) हिंद डीज़ल किला, फ़िरदौस खान, वाहिद खान, कमाल खान, सुल्तान खान, अमन खान, राकिब, गुफरान, दानिश, स्टार रेफ्रिजरेशन बलुआघाट से इरफान खान समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को क्षेत्र की गौरवशाली परंपरा बताते हुए कहा कि इस उर्स से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ-साथ एकता और भाईचारे का संदेश भी मिलता है।

न्याय के लिए भटक रही महिला, ससुरालियों के प्रताड़ना से सहमी पहुँची कोर्ट

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया विशुनपुरा ब्लॉक के नेबुआ नौरंगिया के रामनगर खपरधिक्का निवासी हसीना खातून न्याय के लिए संघर्षरत हैं। उनकी शादी 2007 में खड्डा थाना क्षेत्र के बरवा रतपुर निवासी ह्रीफ अंसारी से हुई थी।शादी के पांच साल तक सब कुछ सामान्य रहा। 2012के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में मोटरसाइकिल औरअन्य सामान की मांग शुरू कर दी। हसीना के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज कीजाने लगी।22 मार्च 2019 को ससुरालियों ने हसीना को पीटकरघर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उनके मायके वालोंको भी धर्मकियां दी गई। पीड़िता ने कई बार थाना खड़ामें शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर हसीना ने अदालत का रुख किया।अब ससुराल पक्ष उन पर वाद वापस लेने का दबाव बना रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जारही हैं। गुरुवार को हसीना ने जिलाधिकारी और पुलिसअधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

गांजे की खेप के साथ दो युवक गिरफ्तार, पुलिस की सतर्कता से नशे का नेटवर्क ध्वस्त

देवरिया। जनपद देवरिया में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गौरीबाजार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस ने 7 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा के साथ दो युवकों को धर दबोचा। पकड़ी गई मादक पदार्थ की यह खेप बाइक से पश्चिमी रेलवे ढाला मार्ग पर ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रमेश यादव पुत्र संतोष यादव एवं सूरज पुत्र राधेश्याम, दोनों निवासी अतरडीहा थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से बरामद गांजा की अनुमानित बाजार कीमत 65,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। दोनों अभियुक्त एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल (यूपी 52 BU 2869) से गांजा की आपूर्ति कर रहे थे। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार वर्मा तथा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में की गई। टीम में प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिन्होंने योजनाबद्ध ढंग से यह जाल बिछाया और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना गौरीबाजार में इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में जिला प्रशासन, डीएम एसपी ने किया तटबंधों का निरीक्षण

जिला प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, कटाव व आपदा प्रबंधन पर नहीं चलेगी लापरवाही

देवरिया।

बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के साथ जनपद के संवेदनशील तटबंधों और बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा कर तैयारियों की जमीनी पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कटाव रोकने के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने रुद्रपुर तहसील अंतर्गत छपरा बुजुर्ग, जंगल भुसवल, तिघरा मराक्षी और पिड़रा क्षेत्र के तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ को निर्देशित किया कि कमजोर बिंदुओं की तत्काल मरम्मत कराई जाए और संवेदनशील स्थलों की 24

घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से पहले सभी सुरक्षा इंतजाम पूर्ण होने चाहिए, ताकि जनहानि या व्यापक क्षति से बचा जा सके।

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पिड़रा गांव में ग्रामीण चौपाल का आयोजन कर स्थानीय निवासियों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की बाढ़ राहत योजनाओं, शिविर व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित स्थानों की जानकारी दी और अपील की कि बाढ़ की स्थिति में अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। चौपाल में ग्रामीणों ने विगत वर्षों में आई बाढ़ के दौरान उत्पन्न समस्याएं भी साझा कीं, जिन पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया। बरहज तहसील क्षेत्र के महेन बाबू और बिनोवापुरी गांवों में राप्ती नदी के किनारे स्थित तटबंधों व कटाव रोधी कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राप्ती और घाघरा दोनों नदियों के किनारे मौजूद संवेदनशील स्थलों की सूची बनाकर वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और उपकरणों तथा नावों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। छितुपुरङ्गभागलपुर क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे चल रहे कटाव निरोधी कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच की और चेतावनी दी कि समय से कार्य पूरे न होने की स्थिति में संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। निरीक्षण दल में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेंद्र सिंह, संबंधित उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

सरपतही में युवक पर हमला : चाकू से किया वार, सिर समेत कई जगह चोट,आरोपी फरार, मुकदमा दर्ज

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सरपतही गांव में रात एक युवक पर चार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित आयांशु शुक्ल पडरौना से पैदल अपने घर लौट रहा था।नहर के पास स्थित सामुदायिक भवन के निकट रात9 बजे चार लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।आयांशु के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई। परिजन घायल आयांशु को जिला अस्पताल पडरौना लेगए। वहां प्राथमिक उपचार के साथ एक्स-रे और अन्यजांच की गई। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के अनुसार पीड़ित की शिकायत पर शाम को मुकदमा,दर्ज किया गया है, जंगल, जगदीशपुर, गांव के अवधेश जोशी, अमन और आकाश आरोपी हैं। पुलिस आरोपियोंकी तलाश कर रही है।

क्षेत्रीय विधायक ने किया इंडियन डेरी फार्म का उद्घाटन

तमकुही राज कुशीनगर । तमकुही विकास खण्ड के चन्द्रौटा में बनी इंडियन डेरी फार्म का उद्घाटन बृहस्पतिवार की शाम क्षेत्रीय विधायक ने किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में इस व्यवसाय से किसानों की उन्नति होगी दुधारू को पशुओं को चारा खिलाकर उद्घाटन करते हुऐ दुधारू पशुओं को लाने की अपील की। क्षेत्र में डेरी फार्म पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ चलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। यहा दुधारू पशुओं के लिए गोशाला बनाई गई है। उन्होंने कहा डेरी खुलने से क्षेत्र के लोगो को लाभ मिलेगा साथ ही इससे व्यसाय बढ़ेगा। कार्यक्रम में भाजपा नेता अजय राय,दिवाकर मणि,श्रीनिवास राय, कन्हैया शर्मा, रामबृक्ष गिरी, राणा प्रताप सिंह,अभिषेक तिवारी,नवनीत तिवारी, अरविन्द सिंह, महन्थ सिंह,पंकज तिवारी,छबीला गुप्ता,सावीर अंसारी, इम्तियाज अंसारी,अब्दुल अली,विष्णु देव गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नवनीत तिवारी ने किया।

चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने पर होगी सेवा समाप्त-डीपीओ

कुशीनगर।

जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि लाभार्थियों की ई-केवाईसी व चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हिदायत जारी की गई है। 30 जून 2025 तक शत-प्रतिशत कार्य नही करती है तो उनका जून माह का मानदेय रोक दिया जाएगा। साथ ही सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है। बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पुष्टाहार पाने वाले बच्चों, धात्री महिलाओं व गर्भवती का चेहरा प्रमाणीकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्य जुलाई से पहले ही पूरा करना है।

जिन लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण होगा, जुलाई में उन्हें ही पुष्टाहार वितरित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 10 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर 10 दिन में शत प्रतिशत कार्य नही किया तो सेवा समाप्ति के लिए तैयार हो जाए।

फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी न होने पर नही मिलेगा अनुपूरक पोषाहार का लाभ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार में पारदर्शिता लाने यथा पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों को ही अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के उद्देश्य से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार अब 01 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केन्द्र के जिन लाभार्थियों का फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी नहीं होगा तब तक उसको आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार का लाभप्राप्त नही होगा।

कुशीनगर। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार में पारदर्शिता लाने यथा पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों को ही अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के उद्देश्य से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार अब 01 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केन्द्र के जिन लाभार्थियों का फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी नहीं होगा तब तक उसको आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार का लाभप्राप्त नही होगा। फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी हेतु लाभार्थी को उनके आधार से लिक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा तथा आधार सत्यापन के पश्चात किया जायेगा। लाभार्थी का चेहरा स्क्रैन करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) का कार्य पूर्ण किया जायेगा। तब वह पूर्ण रूप से पोषाहार सहित अन्य लाभा पाने हेतु पजीकृत हो जायेगा। जनपद की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 30 जून 2025 तक शत प्रतिशत फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी कराए जाने के निर्देश दिये गये है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने लाभार्थियों से अपील की है कि सम्बन्धित आगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होकर आगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क स्थापित करते हुए फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी करा ले। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाओं को निर्देश जारी कर दिये गये है कि अपने-अपने परियोजना ओर परिक्षेत्र में 30 जून 2025 तक अभियान चलाकर शासन के मंशानुार उक्त कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण कराए।

डॉ. अंबर खान ने रचा इतिहास, MRCOG परीक्षा पास कर जौनपुर का नाम किया रोशन

जौनपुर। जनपद जौनपुर की होनहार महिला चिकित्सक डॉ. अंबर खान ने चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए MRCOG (Member of Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वे जिले की पहली महिला चिकित्सक बनी हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परीक्षा पास की है। MRCOG परीक्षा को लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है और इसकी कठिनता के कारण इसे विश्व स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता माना जाता है। डॉ. अंबर की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस सफलता पर डॉ. अंबर खान ने कहा, यह केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरे जौनपुर की जीत है। मैं चाहती हूं कि मेरी यह सफलता अन्य बेटियों और महिला डॉक्टरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। उनकी इस सफलता से न केवल उनके परिवार में बल्कि चिकित्सा जगत में भी उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई है। जौनपुर IMA एसोसिएशन सहित कई चिकित्सा संगठनों ने उन्हें बधाई दी है और सम्मानित करने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक क्षण जौनपुर के चिकित्सा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। डॉ. अंबर खान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी मंज़िल कठिन नहीं।

पोखरी के कूड़े के ढेर में लगा आग, धुंआ धुंआ चौराहा व गांव

तमकुही राज कुशीनगर । पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव पटहेरिया के पोखरी कूड़ो के ढेर में आग लगने से पूरा चौराहा व गांव धुआं धुंआ हो गया।लोगों घर से बाहर धुंआ के चलते हो गए। बाद में सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाया गया फिर लोगों आग से निजात पाये। पटहेरिया के सार्वजनिक पोखरी कुछ स्थानीय दुकानकर व गांव के लोग प्रतिदिन कूड़ा फेकते है।जिससे पटहेरिया-तुर्कपट्टी पर स्थित पोखरी कूड़ा के ढेर से भर गई है।गुरुवार की शाम किसी व्यक्ति ने उस कूड़े के ढेर में चुपके से आग लगा दिया।जिससे एकाएक आग के गुब्बार के साथ धुंआ से चौराहा व गांव भर गया।पुरवा हवा चलने से पूरा धुंआ आसपास के घरों में भर गया और लोग को सास लेने में परेशानी हो गयी और महिला पुरुष हर से बाहर निकल गये।बाद में सूचना पर पहुँचे फायरब्रिगेड के जवानों ने एक घण्टे के भारी मशक्कत के बाद आग बुझाया।जिससे लोगों को धुंआ से राहत मिली।सनद हो कि इस ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन केंद्र के बाद कुछ लोग मनबढ़ई से पोखरी मैए कूड़ा फेंक कर गंदगी फैल रहे है।पीड़ित लोगो ने प्रशासन से कूड़ा फेंकने वाले के विरुद्ध कार्यवाई की मांग की है।

मामूली गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में सूचीबद्ध कंपनियों का हाल जानिए

मुंबई।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 253.62 अंक गिरकर 81191.04 पर खुला। जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 73.95 अंक गिरकर 24738.10 पर खुला। हालांकि, बाद में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और वे सपाट कारोबार कर रहे थे। बीएसई बेंचमार्क 39.09 अंक बढ़कर 81,483.75 पर और निफ्टी 22.70 अंक बढ़कर 24,835.70 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।

किसे फायदा-किसे नुकसान?

सेंसेक्स की कंपनियों में से टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, इंफोसिस, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील और पावर ग्रिड प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर रहे। टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टूब्रो लाभ में रहे।

एशियाई बाजारों में आई गिरावट

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग नकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार मिले-जुले रुख पर बंद हुए।

क्या है विशेषज्ञों की राय?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की खबरें आने तक निफ्टी के लिए 24,500-25,000 का दायरा बरकरार रहने की संभावना है। अगर तनाव कम होने की खबरें आती हैं, तो निफ्टी इस दायरे के ऊपर निकल जाएगा। अगर तनाव बढ़ने की खबरें आती हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में परेशानियों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, तो निफ्टी के लिए 24,500 स्तर पर बने रहना मुश्किल होगा। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत तापसे ने बाजार खुलने से पहले कहा कि पश्चिम एशिया के हालात गंभीर बने हुए हैं। इससे घरेलू शेयर बाजारों में नरमी या कमजोरी देखी जा सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतें होंगी, जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही बढ़ रही हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी।

अमेरिकी फेडरल बैंक ने दरों को स्थिर रखने के निर्णय लिया। इसके कारण यह घबराहट जारी रहने की संभावना है, लेकिन साल के अंत तक दो बार दरों में कटौती की उम्मीद है।

ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर 76.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.27 प्रतिशत गिरकर 76.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 890.93 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 1,091.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 138.64 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,444.66 पर बंद हुआ। निफ्टी 41.35 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,812.05 पर बंद हुआ।

फ्रांस से समझौता : भारत में बनेगा फाल्कन 2000 जेट, रिलायंस इन्फा की दसॉ के साथ ऐतिहासिक करार; नागपुर बनेगा हब

नई दिल्ली । रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने वैश्विक बाजारों के लिए भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए फ्रांस की दिग्गज कंपनी दसॉ एविएशन के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों ने बुधवार को पेरिस एयरशो के दौरान इसकी घोषणा की। यह साझेदारी भारत की वैमानिकी विनिर्माण (एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग) क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत इस ऐतिहासिक समझौते से अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील के साथ अगली पीढ़ी के बिजनेस जेट बनाने वाले देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। दसॉ एविएशन ने कहा कि पहली बार वह फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 जेट का विनिर्माण करेगी। फाल्कन 2000 जेट के लिए अत्याधुनिक असेंबली लाइन महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित की जाएगी। यह फ्रांस के बाहर पहला ऐसा उत्कृष्टता केंद्र होगा। दसॉ एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा, यह नया समझौता एक बार फिर हमारी मेक इन इंडिया प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करता है। समझौता संयुक्त उद्यम को फ्रांस के बाहर फाल्कन असेंबली के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा। नई असेंबली लाइन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करेगी। पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 वर्ष 2028 तक बनकर तैयार होगा।

यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, ट्रंप की टैरिफ नीति से विकास दर भी थमी

वॉशिंगटन। यूएस फेडरल रिजर्व ने गुरुवार सुबह अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों को 4.25-4.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा और कोई बदलाव नहीं किया। इससे साफ है कि अमेरिका ने बदलते आर्थिक परिदृश्य में सतर्कता बरती है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला अधिक रोजगार और स्थिर मुद्रास्फीति के दोहरे लक्ष्य का समर्थन करना है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपने बयान में कहा कि वह ब्याज दरों में कोई और बदलाव करने से पहले आने वाले डेटा, आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन का आकलन करेगी।

फेड के आर्थिक अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष जीडीपी वृद्धि का औसत पूर्वानुमान 1.4 प्रतिशत और अगले वर्ष के लिए 1.6 प्रतिशत है। ये मार्च में किए गए अनुमानों से थोड़ा कम है। पिछले वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन टैरिफ से पहले व्यवसायों द्वारा आयात बढ़ाने के कारण पहली तिमाही में जीडीपी में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि, निजी घरेलू अंतिम खरीद (पीडीएफपी), जिसमें शुद्ध निर्यात, इन्वेंट्री और सरकारी खर्च शामिल नहीं हैं, पहली तिमाही में 2.5 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़ी। मुद्रास्फीति पर, पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति अभी भी फेड के 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। औसत अनुमान में मुद्रास्फीति 2026 में 2.4 प्रतिशत और 2027 तक 2.1 प्रतिशत तक घटने की उम्मीद है। फेड ने व्यापार, आव्रजन, राजकोषीय और नियामक परिवर्तनों की अनिश्चितता को भी स्वीकार किया। मध्य पूर्व में संघर्ष को लेकर चिंता बनी रहने के कारण गुरुवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई। तनाव को बढ़ाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल के साथ संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने की संभावना की चेतावनी दी, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता ने आत्मसमर्पण के अमेरिकी आह्वान को खारिज कर दिया। इससे संघर्ष लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। एशियाई कारोबार में, जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 0.7 प्रतिशत गिरकर 38,619.17 पर आ गया। जापान की निप्पॉन स्टील कॉर्प के शेयरों में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंग सेंग तकनीक से संबंधित शेयरों की भारी बिक्री के कारण 2 प्रतिशत गिरकर 23,231.48 पर आ गया, जबकि शंघाई कंपोजिट 0.9 प्रतिशत गिरकर 3,359.78 पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 8,528.30 पर थोड़ा बदला और दक्षिण कोरिया में कोस्पी 0.4 प्रतिशत गिरकर 2,960.81 पर आ गया।

भारत दे सकता है यूके की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, पीयूष गोयल ने कहा- व्यापार समझौते से मजबूत होंगे रिश्ते

नई दिल्ली । वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया ग्लोबल फोरम में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया संकटों और चुनौतियों से भरी है। फिर भी भारत स्थिरता, तेज विकास के दौर में है। यहां के लोग अपने शांत स्वभाव के कारण पूरे विश्वभर में जाने जाते हैं। चार करोड़ भारतीय विश्व के अलग-अलग देशों में रहते हैं, जिन्हें उनकी प्रतिभा और कौशल के लिए पहचाना जाता है। उद्योग मंत्री ने यूके और भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसे मुफ्त में दिए जाने वाला कहा न्यायपूर्ण नहीं है, भारतीय यूके में जाकर वहां की अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ने का काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एफटीए का फैसला इस बार नई सरकार के आने के बाद उठाया गया है। पिछले तीन वर्षों से इस पर चर्चा चल रही थी। एफटीए के तहत भारत 90 प्रतिशत ब्रिटिश वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेगा, जिसमें 85 प्रतिशत दस वर्ष की अवधि में पूरी तरह से शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके बदले में ब्रिटेन ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ को कम करने पर सहमति जताई है। इससे 99 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पीयूष गोयल दो दिवसीय यूके दौर पर हैं। वहां उन्होंने ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री लिसा नंदी से मुलाकात की । गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक से संबंधित पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लीसा नंदी के साथ अच्छी चर्चा हुई। दो महान लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अधिक अवसरों की खोज की। हमारे जीवंत द्विपक्षीय संबंधों के एक आवश्यक स्तंभ, अधिक सांस्कृतिक सहयोग और रचनात्मक अदान-प्रदान के लिए रास्ते तलाशे।

माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों पर छंटनी का संकट, हजारों की जा सकती है नौकरी; कटौती की योजना बना रही कंपनी

वाशिंगटन । माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों पर छंटनी का खतरा मंडराने लगा है। दिग्गज टेक कंपनी अपने हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों की कटौती खासकर बिक्री विभाग में की जाएगी। ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा निवेश कर रही है और अपने कर्मचारियों की टीम को छोटा और असरदार बनाना चाहती है। इससे पहले मई में भी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने एआई में अपने निवेश को बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य अपने नेतृत्व को मजबूत करना है, क्योंकि विभिन्न उद्योगों की कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई को तेजी से शामिल कर रही हैं। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा था कि आने वाले वर्षों में जनरेटिव एआई और नई तकनीकों की वजह से कंपनी के कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 80 बिलियन डॉलर के खर्च की योजना बनाई है, जिसमें से ज्यादातर पैसा डेटा सेंटर्स बनाने में खर्च किया जाएगा, ताकि एआई सेवाएं बेहतर हो सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, नई छंटनी की घोषणा अगले महीने यानी जुलाई की शुरुआत में हो सकती है, क्योंकि तब माइक्रोसॉफ्ट का वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नौकरियों में कटौती सिर्फ बिक्री टीम तक सीमित नहीं होगी, अन्य विभागों पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी जाएगी। बता दें कि जून 2024 तक माइक्रोसॉफ्ट के पास 228,000 कर्मचारी थे।

भारत में इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी अमेजन

नई दिल्ली।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन ने अपने अखिल भारतीय परिचालन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 2025 में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। अमेजन ने कहा, निवेश से नेटवर्क विस्तार एवं उन्नयन में सहायता मिलेगी, जिससे ग्राहकों को अधिक तेजी से और अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान की जा सकेगी। साथ ही प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों व सहयोगियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। कंपनी ने 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि यह नया निवेश परिचालन नेटवर्क बनाने में किए गए निवेश के अतिरिक्त है, जो कंपनी को समूचे भारत में सभी सेवा योग्य क्षेत्रों तक आपूर्ति करने में मदद करेगा। अमेजन ने साथ ही कहा कि वह आपूर्ति करने वाले सहयोगियों और साझेदारों को सचेत करने और उन्हें आराम के लिए उचित समय देते रहेगा। साथ ही नवीनतम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास जारी रखेगा। कंपनी ने हाल ही में, 2025 के अंत तक चिकित्सकीय शिविरों के माध्यम से 80,000 से अधिक आपूर्ति सहयोगियों व साझेदारों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेजन के उपाध्यक्ष (संचालन) अभिनव सिंह ने कहा, ''ये नवीनतम निवेश हमारे परिचालन को निरंतर विस्तारित और उन्नत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान, दुबई के बैंकों से लिया 1 अरब डॉलर का कर्ज

बिजनेस डेस्क । गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अब दुबई के बैंकों से 1 अरब डॉलर (लगभग 8,600 करोड़) का नया कर्ज लिया है। यह फंड 'सिंडिकेटेड टर्म फाइनेंस' के तहत पांच साल की अवधि के लिए लिया गया है, जिसे कई बैंकों ने मिलकर फाइनेंस किया है। यह फंडिंग एशियाई विकास बैंक द्वारा आंशिक रूप से गारंटीशुदा है। एडीबी के उन्नत संसाधन संग्रहण एवं उपयोग सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई यह गारंटी पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर फाइनेंसरों का भरोसा दिलाने में मदद कर रही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह डील पश्चिम एशियाई वित्तीय बाजार में पाकिस्तान की करीब ढाई साल बाद वापसी है। इससे क्षेत्रीय बैंकों के साथ नई साझेदारी की शुरुआत भी हुई है। पाकिस्तान के आर्थिक सलाहकार खुर्रम शहजाद ने इसे ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि 2023-24 में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से दिवालिया होने से बचा था। हाल के महीनों में देश ने चालू खाता अधिशेष और खर्च नियंत्रण जैसे संकेतकों में कुछ सुधार दिखाया है। अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान का चालू खाता अधिशेष 1.8 अरब डॉलर रहा।

एक नजर

8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर एक करोड़ कर्मियों-पेंशनरों को संशय, जेसीएम ने लिखा पत्र

नई दिल्ली । नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी फॉर सेंटर गवर्नमेंट एम्पलाइज जेसीएम ने 18 जून को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र में जेसीएम की तरफ से यह मांग की गई है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) तैयार किए गए हैं, उन्हें सर्कुलेट यानी प्रसारित किया जाए। डीओपीटी ने जेसीएम को सूचित किया था कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूप दिया जा रहा है। डीओपीटी ने टीओआर के लिए जेसीएम से सुझाव मांगे थे। जेसीएम ने बहुत पहले ही वे सभी सुझाव, डीओपीटी को सौंप दिए थे। टीओआर के लिए सुझाव सौंपे जाने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों की सर्वोच्च इकाई जेसीएम के साथ कोई भी संचार नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को संशय हो रहा है।

जेसीएम के सुझावों को कितनी मिली तव्वजो...

जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है, कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को कितनी तव्वजो मिली है, इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर असमंजस में हैं। उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति है। इतना ही नहीं, टीओआर का दस्तावेज, जेसीएम तक नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में सरकार की घोषणा और विश्वसनीयता को लेकर संशय बन रहा है। कर्मचारी, आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सेवारत कर्मियों के अलावा पेंशनर भी आठवें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं हैं। वजह, उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि आठवें वेतन आयोग का पेंशनर को फायदा होगा या नुकसान। फाइनेंस बिल के चलते भी पेंशनर, चिंतित हो गए थे। आठवें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। महंगाई राहत डीआर का क्या होगा, ऐसे कई सवाल पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं। उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है।

कर्मियों/पेंशनरों के सभी संदेह दूर होने चाहिए...

इन सबके चलते जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल की गई है, उसे स्पष्ट किया जाए। टीओआर में लिखी बातें, बड़े स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाई जाए। इससे कर्मचारियों का उत्साह बना रहेगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर उनमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी। आठवें वेतन आयोग में किस तरह से वेतन तय होगा, रिवाइज सेलरी का प्रारूप क्या रहेगा, आदि बातों का स्पष्ट होना आवश्यक है। कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी संदेह दूर होने चाहिएं। जेसीएम ने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि आठवें वेतन आयोग की कमेटी, जल्द से जल्द गठित हो। अगर सरकार उक्त बातों को ध्यान में रखकर टीओआर को सार्वजनिक करती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों में सरकार के प्रति भरोसा बना रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी, उत्साह के साथ अपना काम करेंगे। इस पत्र की कॉपी, सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव डीओपीटी और सभी मान्यता प्राप्त यूनियन के महासचिव को भेजी गई है।

10 फरवरी को हुई थी जेसीएम की बैठक...

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगने के बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की। इसमें आठवें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से आठवें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व कामरेड शिव गोपाल मिश्रा (सचिव) ने किया था। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से एम राघवैया (नेता), सी. श्रीकुमार, (सदस्य स्थायी समिति), जेआर भोसले, (सदस्य स्थायी समिति), गुमान सिंह (सदस्य स्थायी समिति), बीसी शर्मा, (सदस्य स्थायी समिति), रूपक सरकार, (सदस्य स्थायी समिति) और तापस बोस (सदस्य स्थायी समिति) उपस्थित रहे।

जेसीएम के प्रतिनिधियों ने दिए थे ये सुझाव...

जेसीएम के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में तीन इकाइयों की जगह अब न्यूनतम पांच इकाइयां होनी चाहिएं। आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा, जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवनयापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई।

टीओआर के लिए दिया गया था ये मसौदा...

जेसीएम की अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, अन्य लाभ/सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन/ग्रेयुटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना, आदि शामिल था। जेसीएम की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिए गए, उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, दोनों शामिल थे। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवनयापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी विचार किया जाए

पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉ. अकरोयड फॉर्मूले में संशोधन के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए, जेसीएम की बैठक में आठवें वेतन आयोग के टीओआर के लिए सरकार को यह सुझाव भी दिया गया। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 03 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। 8वीं सीपीसी को गैर-व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल-1 को लेवल-2 के साथ और लेवल-3 को लेवल-4 और लेवल-5 को लेवल-6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए।

न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश

एमएसीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और एमएसीपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसे भी संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का प्रतिशत, तुरंत निर्धारित हो। 7वीं सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए, जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, संदर्भ शर्तों में इनके समाधान पर विचार किया जाए। जेसीएम सदस्यों ने इसे जरूरी विषय बताया है। पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति, ग्रेयुटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, हर पांच साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी संदर्भ शर्तों के लिए भेजा गया।

डीओपीटी सचिव के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया...

मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच समानता, यह सुझाव भी भेजा गया है। एक जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 (अब 2021) के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, डीओपीटी सचिव के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया है। सीजीएचएस से संबंधित मामलों को लेकर एफएमए की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशनभोगियों सहित कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को कैशलेस/परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना, इन्हें भी संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए।